

सार समाचार

सरकार जेएंडके में चुनाव कराने को तैयार

नई दिल्ली एजेंसी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर में शासन चलाने के लिए राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब सरकार वहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में सांविधिक संकल्प पेश किया। संकल्प को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। संकल्प पारित कराने के लिए आम तौर पर पहले चर्चा की जाती है और उसके बाद इसे पारित कराया जाता है, लेकिन इस बार संकल्प पहले पारित हो गया था और उसके बाद उस पर सदन में चर्चा करायी गयी। इसको लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर टीका-टिप्पणी भी की और कहा कि वह सदन में नये-नये तरीके अपना रही है। राज्य में राज्यपाल शासन की छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये सिंह ने कहा कि केंद्र ने राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य में सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं है।

सेना ने सिक्किम में 2,500 से ज्यादा सैलानियों को बचाया

गंगटोक एजेंसी। पूर्वी सिक्किम में भारत चीन सीमा के नजदीक सेवनटीन्थ माइल इलाके के पास बर्फबारी के बाद फंसे 2,500 से ज्यादा सैलानियों को भारतीय सैनिकों ने बचाया है। पूर्वी सिक्किम के जिलाधिकारी कपिल मोघान ने बताया कि सैलानी शुक्रवार शाम नाथूला दर्रा और त्सोगो (चांगू) झील से लौट रहे थे और बर्फबारी की वजह से क्षेत्र की सड़कें अवरोध हो गई थीं। इससे 300-400 से ज्यादा असीन्य वाहन जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर फंस गए थे। मोघान ने बताया कि सेना तुरंत हरकत में आई और सैलानियों को बचा लिया। उन्हें सेवनटीन्थ माइल इलाके में स्थित शिविर में ले जाया गया और खाना तथा दवाएं दी गईं। पर्यटकों को राज्य की राजधानी भेजे जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं।

गाजीपुर पथराव: सिपाही की मौत के मामले में अब तक 20 गिरफ्तार

खगड़िया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिस के एक सिपाही की मृत्यु के मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था और इस मामले में नौ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने रविवार को यहां बताया कि गाजीपुर में शनिवार को हुए पथराव में हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप सिंह वत्स की मृत्यु अत्यन्त दुःखद है। इस मामले में दर्ज हुए तीन मुकदमों में अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत 32 नामजद और 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी पर एफएसए लगाया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर धारा लगाकर कार्रवाई किया जाएगी। योगी ने पथराव में सिपाही की मौत पर बताया दुःख, 50 लाख मुआवजे का एलान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को स्थानीय प्रशासन की नाकामी करार देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की रैली की वजह से प्रशासन और पूरे खुफिया विभाग को पता था कि कहाँ पर किसका धरना-प्रदर्शन होने वाला है।



उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शनिवार को आयोजित एक रैली में महाराजा सुहेल देव राजभर पर डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उग्र के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रेलवे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा।

बड़ी खोज, बनाया ऐसा बिस्कुट जो रोकेगा कैंसर

वाराणसी। शूगर के गंभीर और सेकंड स्टेज कैंसर रोगियों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) ने बड़ी खोज की है। बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक ऐसा बिस्कुट बनाया है जो मधुमेय रोगियों के शरीर में इंसुलिन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ागा। यह बिस्कुट कैंसर के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के एचओडी प्रो. अनिल चौहान ने छह महीने तक गहन शोध के बाद यह बिस्कुट तैयार करने में सफ लता पाई है। उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने के लिए नेचुरल स्वीटनर स्टीविया और मेथी को विशेष अनुपात में प्रयुक्त किया गया है। मेथी की विशिष्ट मात्रा स्टीविया के साथ मिल कर ट्राइवोलिन और इंसुलिन बनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया से ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। स्टीविया और मेथी का यह संयोजन हाइपो कोलेस्ट्रॉलमिक एंटी वैकटीरियल के जरिए कैंसर के रोगाणुओं को नष्ट करता है। गणितीय अनुपात में मैदा और सप्रेटा दूध के पाउडर बिस्कुट के बेस बनाया गया है। बिस्कुट में इन सब की एक निश्चित मात्रा शरीर में पहुंचने के बाद पीआई-थ्री काइनेज इंजाइम, फोरे

हाइड्राक्सी इसोल्युसिन के माध्यम से पॉक्रियाटिक सेल (अनाशय कोशिकाओं) को री-जेनरेट करता है। ये तत्व शरीर में एंटी डायबेटिक, एंटी कैंसर और हेप्टोप्रोटेक्टिव के रूप में काम करते हैं। **चीनी से सौ गुना मोटी है स्टीविया की पत्ती** स्टीविया एक ऐसा नेचुरल स्वीटनर है जो चीनी की तुलना में पचास से सौ गुना अधिक तक मीठा हो सकता है। हमारे पर्यावरणी परिवेश में इसकी उपलब्धता भी बहुत कठिन नहीं है। स्टीविया में सामान्य चीनी जैसे किसी भी प्रकार के कोई दुरुगुण नहीं होते। **लागत है सामान्य बिस्कुट के जितनी** खास तरह के बिस्कुट को तैयार करने में लागत बेहद कम आई है। बाजार में बिकने वाले सामान्य बिस्कुट की दर पर ही इसे जरूरतमंदों को सुलभ कराया जा सकता है। बिस्कुट एक महीने और विशेष पैक में छह महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। **मैसूर के अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में मिली खास तबज्जो** इसी महीने मैसूर में हुए खाद्य वैज्ञानिकों में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में प्रो. चौहान ने अपने इस नवीनत शोध को निश्चित मात्रा शरीर में पहुंचने के बाद पीआई-थ्री काइनेज इंजाइम, फोरे

कर्म माफी पर प्रधानमंत्री की किसानों से अपील कांग्रेस के लॉलीपॉप से बचें

वोट बटोरने के लिए लुभावने वादों का हथ्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखने लगा

वाराणसी एजेंसी। तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले फैसलों से समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं हो सकता। चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की नौद उड़ गई है। आपके आशीर्वाद से इनको सही जगह पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए शनिवार को कहा कि वोट बटोरने के लिए लुभावने वादों का हथ्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखने लगा है और वहां काला बाजारी करने वाले मैदान में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले वादों और फैसलों से देश की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। मोदी ने यहां राजकीय मेडिकल कालेज का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में किसानों के संदर्भ में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बदलते ही वहां अब खाद और यूरिया के लिए कतारें लगने लगी हैं। लाठियां चलने लगी हैं और काला बाजारी करने वाले मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस को 'लॉलीपॉप' पकड़ाने वाली पार्टी बताते हुए मोदी ने कहा कि कर्नाटक में लाखों किसानों की कर्म माफी का वायदा किया गया था, लेकिन

कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और कर्म माफी के वादे को पूरा करने के बजाय लालीपाप पकड़ा दिया। अभी तक केवल 800 किसानों का ही कर्म माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि 2009 के चुनाव के पहले भी ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ने वालों ने देश भर के किसानों की कर्म माफी का वादा किया था। उन्होंने कहा, '“मैं यहां के किसानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका कर्म माफ हुआ? क्या आपके खाते में पैसा आया? क्या आपको कोई मदद मिली?’’ मोदी ने कहा कि वादा किया, फिर सरकार बनी, लेकिन किसानों को भुला दिया गया। उन्होंने कहा, '“चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की रातों की नौद उड़ गई है। आपके आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आएगा, जब इन चोरों को सही जगह पर ले जाया जाएगा।’’ **'स्वामीनाथन रिपोर्ट पहले लागू हो जाती तो आज किसान कर्जदार ही नहीं होता :** '“कांग्रेस सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया था। आज से 11 साल पहले अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया होता, लागत का डेढ़ गुना दाम तय किया गया होता तो आज किसान कर्जदार होता ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने फाइल दबाए रखी, किसान को दाम नहीं दिया,

मायावती के जन्मदिन पर कई राजनीतिक दलों की भी नजरे

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती का 15 जनवरी को मनाया जाने वाला जन्मदिन इस बार पिछले सालों की अपेक्षा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मनाए जाने वाले इस जन्मदिन पर अन्य राजनीतिक दलों की भी नजर है। वजह, गठबंधन को लेकर होने वाली चर्चाएं हैं। इस लिहाज से सभी की नजर जन्मदिन पर होने वाले आयोजन पर है कि मायावती गठबंधन को लेकर क्या संदेश देती हैं। मायावती काफी समय बाद लखनऊ आ रही हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में उनके आने की संभावना जताई जा रही है। वह अपना जन्मदिन अमूमन लखनऊ में ही मनाती रही हैं। जन्मदिन के मौके पर वह दलित मूवमेंट ऑफ मायावती पुस्तक यानी ब्लू बुक का विमोचन भी करती हैं। उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है।

दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने की कोशिश, तीन परीक्षार्थी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा में नकल करने की कोशिश करने वाले एक परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विक्रम के रूप में हुई है। वह रोहतक का रहने वाला है। इससे पहले शुक्रवार को भी पुलिस ने दो परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार एसआई रामबीर सिंह शाहदरा जिले के पुलिस लाइन में तैनात हैं। इस समय उनकी ड्यूटी सोनिया विहार थाना इलाके के बजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में चल रही है कि एक-दो लोगों ने कोई प्रयास किया हो, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। चूंकि सरकार बनाने को कोई तैयार नहीं था और इस बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट थी, ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं था।

परीक्षार्थियों की तलाश ले रहे थे। इस दौरान परीक्षार्थी विक्रम बायोमेट्रिक कराने के बाद शौचालय में चला गया। शौचालय से लौटने के बाद अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उन्हें शक हुआ तो विक्रम की तलाश लेनी शुरू की। इस दौरान उसकी शर्ट की जेब से सिमकार्ड लगा मोबाइल फोन और बाये कान से ब्लूटूथ मिला। उन्होंने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोबाइल फोन और ब्लूटूथ कब्जे में ले लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। **दो दिन में तीन परीक्षार्थी गिरफ्तार** भर्ती परीक्षा में पुलिस ने दो दिन में नकल करने की कोशिश करने वाले तीन परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है।

शुक्रवार को पुलिस ने दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे प्रवीण को गिरफ्तार किया है। सोनीपत का रहने वाला प्रवीण अपने जानकारी अनिल की जगह परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान पहचान पत्र और फोटो मैच नहीं होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं शुक्रवार को ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करने की कोशिश करने वाले रजत यादव को गिरफ्तार किया। **कड़ी सुरक्षा के बीच फर्जीवाड़े की कोशिश** पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। गेट से लेकर अंदर कमरे तक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक भी कराया

जा रहा है। ताकि किसी परीक्षार्थी की परीक्षा दूसरा कोई नहीं दे सके। इसके बावजूद परीक्षार्थी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही नकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कक्षों के अंदर तक लेकर चले जा रहे हैं। हालांकि परीक्षार्थियों को नकल करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। **पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले** भर्ती परीक्षा में पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रवीण हरियाणा के सोनीपत, गांव बिंदरोली का रहने वाला है। जबकि रजत यादव हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। वहीं विक्रम भी हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है।

श्रीनगर : कांग्रेस एमएलसी के घर से संदिग्ध आतंकियों ने लूटी एके-47 रायफल

एजेंसी, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर में संदिग्ध आतंकियों ने कांग्रेस के एमएलसी के घर से रायफल लूट ली। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कप मच गया। इसके बाद घाटी में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर श्रीनगर में एमएलसी मुजफ्फर अहमद पर्र के घर संदिग्ध आतंकियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान उनके घर पर सुरक्षा में तैनात जवानों की एके-47 रायफल लेकर संदिग्ध आतंकियों वहां से फरार हो गए।

राजस्थान: भाजपा ने सात पंचायत समिति और एक जिला परिषद की सीट पर जीत दर्ज की **एजेंसी, जयपुर।** राजस्थान में 13 पंचायत समिति सदस्यों और एक जिला परिषद सीट पर उपचुनावों में भाजपा ने सात पंचायत समिति और एक जिला परिषद की सीट पर जीत दर्ज की है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से रविवार को घोषित 13 पंचायत समिति सदस्यों और एक जिला परिषद के उपचुनाव के परिणामों में सात पंचायत समिति पर भाजपा, पांच पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 28 दिसम्बर को राज्य में सभी सीटों पर हुए उपचुनाव के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिये मतदान हुआ था। 13 पंचायत समिति में से भाजपा के तीन उम्मीदवारों और एक कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। आयोग ने राज्य के अलवर की एक जिला परिषद, और भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली और सीकर पंचायत समिति के उपचुनाव के लिये इस माह के पूर्व में चुनाव के लिये अधिसूचना जारी की थी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के कारण पंचायती राज संस्थानों में 27 अक्टूबर को होने वाले मतदान को आगे बढ़ा दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए केंद्र तैयार : राजनाथ

नयी दिल्ली, एजेंसी

जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने एवं विकास को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र चुनाव को तैयार है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 लगाए जाने के संबंध में सांविधिक संकल्प पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई भी गलत या अनैतिक कार्य इस सरकार के तहत नहीं होगा। **राज्यपाल के पास नहीं था विकल्प :** राज्य में चुनाव कराने के बारे में कुछ सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आयोग चुनाव के संबंध में

सुरक्षा मांगता है तो हम प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का बचाव करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा की मंशा पर सवाल नहीं किया जा सकता। अगर भाजपा को सरकार बनानी होती तो वह छह महीने के समय में कोशिश कर सकती थी, लेकिन हमने नहीं किया। उन्होंने जोर दिया कि हो सकता है कि एक-दो लोगों ने कोई प्रयास किया हो, लेकिन हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। चूंकि सरकार बनाने को कोई तैयार नहीं था और इस बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट थी, ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं था।



हम लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं : राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने बार-बार अपील की है कि सभी पक्षों से बात करके हम समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। हम दो बार सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर भी गए। उन्होंने कहा कि हम राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके तहत स्थानीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। युवाओं को रोजगार के प्रबंध किए गए हैं और विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संदर्भ में राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वयं एक बार राज्यपाल से पूछा कि क्या वहां कोई भी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है? मैंने अखबार में पढ़ा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों

पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं, लेकिन सुबह मैंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का बयान पढ़ा कि कांग्रेस नहीं बनाना चाहती। इसलिए मेरी धारणा बनी कि वहां कोई भी सरकार नहीं बनाना चाहता। राज्यपाल ने भी कहा कि कोई भी सरकार नहीं बनाना चाहता है। राज्य में भाजपा और पीडीपी के मिलकर सरकार बनाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आप इसे अस्वाभाविक विवाह कहिए या क्या कुछ भी कहिए। जिसे नैचुरल मैरिज कहा जाता है वह भी कब टूट जाए, उसका पता नहीं। सिंह ने कहा कि कश्मीर के लोग हमसे अलग नहीं हैं। कश्मीर की ऐसी हालात देखकर हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। मैंने बार-बार यही कहा है कि मैं कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए तैयार हूं, राजनीतिक दल बताएं कि क्या किया जा सकता। चर्चा में कांग्रेस, तुष्टमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा, राकांपा, राजद, सपा, अन्नाद्रमुक सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया।

संपादकीय

विरोध राजनीति प्रेरित

लोक सभा में तलाक-ए-बिदत या तीन तलाक को गैर-कानूनी बनाने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 का पारित होना निश्चित था। भाजपा को स्वयं लोक सभा में बहुमत है और उसने सारे सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। हालांकि इसके बावजूद विधेयक के पक्ष में केवल 245 सांसदों का मत आना आश्चर्य में डालने वाला है। जाहिर है, स्वयं भाजपा के ही सारे लोक सभा सांसद उपस्थित नहीं थे।



अगर भाजपा एवं राजग के सांसदों ने यही रवैया राज्य सभा में अपनाया तो यह विधेयक फिर लटक जाएगा। वैसे भी राज्य सभा में राजग के पास बहुमत नहीं है। राज्य सभा में कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का समर्थन न मिलने के कारण इसे अध्यादेश के रूप में सामने लाना पड़ा। कांग्रेस सहित कई पार्टियां विधेयक में दोष निकाल रहे हैं लेकिन इसके विरोध में मतदान करने का साहस नहीं कर रहे। बहस के बाद जब मत विभाजन का समय आया

कांग्रेस, राकांपा, सपा, राजद, आईयूडीएफ, तृमूकां, तेदेपा, अन्नाद्रमुक और द्रमुक ने सदन से बहिर्गमन का रास्ता चुना। क्यों? उनको पता है कि यह ऐसा विधेयक है, जिसका सीधे विरोध करना उनके सेवयुत्तर चेहरे पर दाग की तरह होगा। इसके पक्ष में मुस्लिम महिलाओं का एक वर्ग तो है ही, हिन्दुओं के अंदर भी यह भाव है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाकें बिदत को असंवैधानिक करार देने के बावजूद ऐसा करने वालों को रोकने का कोई कानूनी ढांचा तो होना चाहिए। वैसे भी मूल विधेयक में इतना बदलाव किया जा चुका है कि इसका समर्थन करने में समस्या नहीं होगी चाहिए। अब सिर्फ पीडित महिला, उससे खून का रिश्ता रखने वाले और विवाह से बने उसके रिश्तेदार ही प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। दूसरे, पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को सुनह कराने और आरोपित को जमानत देने का भी अधिकार होगा। थाने से जमानत नहीं होगी। और तीन, कानून का उल्लंघन करने पर यानी नियम के विरु द्न एक बार में या फोन या मैसेज या पत्र द्वारा तीन तलाक देने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। तीन तलाक से पीड़ित या भविष्य में पीड़ित होने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और दोषी पतियों को कानून के शिकंजे में कसने के किसी कदम का विरोध होना ही नहीं चाहिए। जाहिर है, इसके पीछे केवल राजनीति है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता।

निर्मम शिकारी

काले हिरणों के अवैध शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को लेकर अखबारी सुर्खियां अभी सूखी भी नहीं थीं कि यूपी के सरयू घाघरा नदी प्रवाह क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा के अवैध शिकार की खबरें सामने आ गईं। ज्योति रंधावा और उनके साथ पूर्व नेवी अधिकारी की अवैध शिकार के मामले में गिरफ्तारी की खबर से यही लगता है कि इस बाबत जन जागरूकता में काफी कसर रह गई है। पहले से ही दाम्गदार नेवी अधिकारी के पास से 80 कारतूस, एक दूरबीन, राइफल और वन्य जीवों के शिकार के कई और प्रमाण मिले हैं। कठोर वानिकी नियमों और वन्यजीव संरक्षण के बावजूद इतने लंबे-चौड़े विस्तृत जंगलों की चौकीदारी कर पाना काफी मुश्किल है। यहां के जंगल भी काफी विस्तृत हैं और इतने विस्तृत वनों में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं जो कि हमेशा अवैध शिकार करने वाले शिकारियों की निगाहों में चढ़े रहते हैं। हाथी, तेंदुए, गैंडे और इनके अतिरिक्त प्रवासी चिड़िया भी इन शिकारियों की अपेक्षित लक्ष्य होती हैं। हाथी दांत, गैंडों के सींग आदि चीजों की तस्करी काफी ज्यादा होती है। प्रवासी पक्षियों में फ्लेमिंगो पोलिकस और विष्णुत- अमूर फोल्क्लन लगातार अवैध शिकार बनते हैं। वर्ष 2017 में ओलंपिक शूटर और अर्जुन अवार्ड विजेता गुरबीर सिंह संधू के पास से जंगली भालू के दांत पाए गए थे। जंगली जानवरों के शिकार का शौक करने वाला जमाना अब जा चुका है। हमें आवश्यकता है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें क्योंकि प्राकृतिक संतुलन के लिए यह अत्यावश्यक है। सरकार को भी इस तरफ काफी ध्यान देना होगा और वन सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए वन्य अधिकारियों और जंगलों को इनसे सुसज्जित करना होगा। साथ ही जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को जाग्रत और सुरक्षित करना होगा कि जब तक वे वन्यजीव और जंगल मौजूद हैं तभी तक मनुष्यों का अस्तित्व भी मौजूद है। वन्य जीवन के विनाश के साथ ही प्राकृतिक असंतुलन शुरू हो जाएगा जो कि मानव के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा।

ओशो

ज्ञान

ज्ञान है, जो भर तो देता है मन को बहुत जानकारी से, लेकिन हृदय को शून्य नहीं करता। एक ज्ञान है, जो मन भरता नहीं, खाली करता है। हृदय को शून्य का मंदिर बनाता है। एक ज्ञान है, जो सीखने से मिलता है। और एक ज्ञान है जो न सीखने से मिलता है। जो सीखने से मिले, वह कूड़ा-करकट है। जो न सीखने से मिले, वही मूल्यवान है। सीखने से वही सीखा जा सकता है, जो बाहर से डाला जाता है। न सीखने से उसका जन्म होता है। जो तुम्हारे भीतर सदा से छिपा ही है। ज्ञान को अगर तुमने पाने की यात्रा बनाया, तो पंडित होकर समाप्त हो जाओगे। ज्ञान को अगर खोने की खोज बनाया, तो प्रज्ञा का जन्म होगा। पांडित्य तो बोझ है; उससे तुम मुक्त न होओगे। वह तो तुम्हें और भी बांधेगा। वह तो गले में लगी फांसी है, पैरों में पड़ी जंजीर है। पंडित तो कारागृह बन जाएगा तुम्हारे चारों तरफ। तुम उसके कारण अंधे हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिसे भी यह भ्रम पैदा हो जाता है, कि शब्दों को जानकर उसने ज्ञान लिया, उसका अज्ञान पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। तुम उस ज्ञान की तलाश करना जो शब्दों से नहीं मिलता, निःशब्द से मिलता है। जो सोचने-विचारने से नहीं मिलता, निर्विचार होने से मिलता है। तुम उस ज्ञान को खोजना, जो शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। वही ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, वही ज्ञान तुम्हें एक नये नर्तन से भर देगा। वह तुम्हें जीवित करेगा, वह तुम्हें तुम्हारी कब्र के ऊपर बाहर उठाएगा। उससे ही आगो फूल जीवन के। और उससे ही अन्तः परमात्मा का प्रकाश प्रगटेगा। पंडित जानता है और नहीं जानता। लगता है कि जानता है। ऐसे ही, जैसे बीमार आदमी बजाय औषधि लेने के, चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करने लगे। जैसे भूखा आदमी पाकशास्त्र पढ़ने लगे। ऐसे सत्य की अगर भूख हो, तो भूल कर भी धर्मशास्त्र में मत उलझ जाना। वहां सत्य के संबंध में बहुत बातें कही गई हैं, लेकिन सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो कब कहा जा सका है? कौन हुआ है समर्थ जो उसे कह सके? इसलिए गुरु ज्ञान नहीं देता, वस्तुतः तुम जो ज्ञान लेकर आते हो उसे छीन लेता है। गुरु तुम्हें बनाता नहीं, मिटाता है। तुम्हारी याददाश्त के संग्रह को बर्दात नहीं, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारे संग्रह को खाली करता है। जब तुम पूरे खाली हो जाते हो, तो परमात्मा तुम्हें भर देता है। शून्य हो जाना पूर्ण को पाने का मार्ग है।

हिरमोहन मिश्र

लोकसभा विपक्ष से इतना भयभीत हो गया कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पारित पहले हुआ, बहस बाद में हुई। मणिपुर में एक पत्रकार की टिप्पणी एन. बिरेन सिंह की भाजपा सरकार को इतना भयभीत कर गई कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार कर लिया गया। नसीरुद्दीन शाह की छेटी-सी चिंता ऐसा डर वरपा कर गई कि टीवी चैनलों के स्टूडियो और सोशल मीडिया में तथाकथित राष्ट्रवादी फट पड़ने को उतावले हो गए। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापु के अयोध्या में वेश्याओं को रामकथा सुनाने की बात से वहां के धर्म संप्रदाय का एक वर्ग अपवित्र हो जाने की ऐसी आशंका से भर उठा कि हाहाकार मच गया। इसके पहले सबरीमला में हर उम्र की औरतों के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां के समाज का एक वर्ग और कुछ राजनैतिक दल परंपरा टूटने से ऐसे भयभीत हुए कि आंदोलन टूटता ही नहीं। ये तो बस हालिया घटनाएं हैं। भय के सिलसिले लंबे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो आक्रामकता की मिसालें हैं, भय की नहीं। लेकिन गौर से देखेंगे तो ये भयभीत, असुरक्षित मानस की ही परिणतियां हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि यह भय मौजूदा व्यवस्था के शिखर से बहता दिख रहा है, जो समाज में अनेक विभाजनकारी विवृतियों को जन्म दे रहा है।हाल के गृह मंत्रालय के उस आदेश को भी देखेंगे तो लगेगा वाकई यह व्यवस्था भयाक्रांत है, जिसमें 10 सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश में हर किसी के कंप्यूटर खंगालने के अधिकार दे दिए गए हैं। मानो देश का हर नागरिक सता-प्रतिष्ठान के प्रति साजिश में शुमार है। विपक्ष के

ये आरोप बेमानी इसलिए नहीं लगते क्योंकि ऐसी खुफिया ताकझांक की अनुमति देने वाला 2002 का कानून और 2009 के उसके संशोधित रूप में इसके लिए हर एजेंसी को संयुक्त अधिक से अनुमति लेनी पड़ती थी या फिर उसे एक निश्चित सचिव में वजह बतानी पड़ती थी, और वजह न बताई गई तो अनुमति नहीं मिलती थी। सरकार की दलील है कि उसने कोई नया आदेश नहीं दिया, सिर्फ गृह मंत्रालय का बौद्ध कम करने की कोशिश की है। हाल में एनआईए ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर छापे मार कर कथित तौर पर आईएस के माॅडयूल पकड़े तो केंद्र सरकार के ऐसे मामलों में संकटमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल उठे कि इसी वजह से खुफिया ताकझांक की दरकार है। इससे तो कई हलकों में यह शक भी पैदा किया जा रहा है कि अपने आदेश को जायज ठहराने के लिए ये छापे मारे गए। सवाल है कि सरकार को अपने अंतिम वर्ष में आकर ऐसी खुफिया ताकझांक के लिए ऐसा आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी।

२२

२२

२२

डॉ. दिलीप चौबे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया के बाद अफगानिस्तान से भी अपने चौदह हजार सैनिकों में से सात हजार सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले से आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में शून्यता पैदा हो सकती है। दक्षिण एशिया में महाशक्तियां अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही हैं, ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद सबकी निगाहें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। रूस और चार मध्य एशियाई देश-कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत सभी के काबुल में कूटनीतिक-राजनीतिक हित हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का असर बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में तालिबान की भागीदारी का मुद्दा उठाया था। रूस और चार मध्य एशियाई देश-कि अफगानिस्तान में अमेरिकी नीति असफल हो गईहै। इसलिए वह यहां अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। पिछले महीने रूस की पहल पर मास्को में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत बारह देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। रूस और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आईएसआईएस के

विभांशु दिव्याल

बात पिछले दिनों आए भूकंप की है। जो भूकंप कुछ समय से थमे-थमे दिख रहे थे, जो झटके थोड़े रुकके-रुकके लग रहे थे वे एक बार फिर महसूस हुए। रिक्टर पैमाना इस भूकंप की तीव्रता भले ही न माप पाया हो लेकिन कंप-प्रकंपमापी मीडिया ने बताया कि भूकंप था, जबरदस्त था। मीडिया के उछलबच्चों ने अपने-अपने समाचार कक्षों में इसे पूरी शिद्दत से महसूस किया। मीडिया में पूरी बहस हुई, इस बात पर कि भूकंप स्वतः आया था, आदतन लाया गया था, या किसी टाइग्रोग्राफिक गलती की वजह से आ गया था।तो यह भूकंप प्रस्ताव का चोला ओढ़कर आया। भूकंपी प्रस्ताव आप की सरकार ही ला सकती थी, और वही लाई। किसके गुदरे में दम था कि ऐसा प्रस्ताव ला सके और जिसे जो मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत ही उसकी वापसी का ऐलान कर सके। जिसकी मां की मौत पर नरसंहार हुआ हो उसे भारत रत्न से नवाजा जाए तो इसे कैसे सहन किया जाए। अतः इतिहास की इस विराट गलती को सुधारने का कोई विराट प्रयास किया जाए। आप विधायकों ने प्रस्ताव बना लिया कि जिन राजीव गांधी को अपने जीवनकाल में पता भी नहीं था, वह भारत रत्न हैं, उनसे उनकी भारत रत्नीयता छीन ली जाए और भूकंप लाया जाए। भारत की भूकंपी राजनीति अपने प्रसव-पैदाइश काल से ही प्रवेष्ट भूकंपवादी रही है। जैसे ही वह

विपक्षी दल इसे आसन्न 2019 के आम चुनाव में दुरुपयोग

का औजार बता रहे हैं। लेकिन इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार अपने भय और शक-शुबहे को समाज के विभिन्न स्तरों में तारी करना चाहती है, जिसके नजारे तरह-तरह से दिखने भी लगे हैं। दरअसल, डर और दहशत का माहौल इस सरकार के आने के साथ ही शुरू हो गया था। उसके नतीजे मॉब लिचिंग, विविधालयों में टकराव वगैरह के रूप में दिख चुके हैं। लेकिन खासकर 2017 और 2018 के विधानसभा चुनावों और कुछ संसदीय उपचुनावों



से माहौल बदलने लगा। इसमें सबसे ज्यादा असर गुजरात

चुनावों का है, जहां भाजपा जीत तो गई मगर उसे दो अंकों तक सिमट आना पड़ा। वहां उसके खिलाफ कांग्रेस ही नहीं, हार्दिक पटेल, अलेश्या ठाकोर और ज़िम्नश मेवाणी ने भी भाजपा की अजेय शक्ति को चुनौती दी थी यानी समाज का एक बड़ा वर्ग जो मौन था, या उस पर कुछ दहशत का माहौल तारी था, उसने उस माहौल को झटक दिया। इसमें शायद हार्दिक पटेल की राजद्रोह में गिरफ्तारियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वजह यह कि राजतंत्र का भय दिखाकर और लालच देकर हार्दिक को तोड़ा नहीं जा सका। फिर, कर्नाटक के चुनावों ने यह भरोसा भी बहाल कर दिया कि भाजपा की चुनावी मशीन को जोड़तोड़ के तरीकों में भी मात दी जा सकती है। उसका असर शायद यह भी हुआ कि बेवैनी महसूस कर रहे अफसरशाहां और अर्थशास्त्रियों ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। नोटबंदी के दौर में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रह्मण्यम और

वैश्विकी

काबुल पर सबकी निगाहें

विस्तार से चिंतित हैं। रूस सीरिया में असद सरकार के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया था। उसके इस कदम से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) रूसी नेतृत्व से नाराज है। दो हजार सोलह में रूस के

नई दिल्ली यह भी चाहेगा कि काबुल में ऐसी सरकार का गठन न हो जिसका झुकाव पाकिस्तान की ओर हो क्योंकि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग होगा तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन सकता है

सैंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में आईएस ने आतंकी हमला करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। हमले के बाद रूस अपनी सुरक्षा को लेकर सावधान हो गया है। रूसी नेतृत्व जानता है कि आईएस ने अफगानिस्तान में विस्तार कर लिया तो वह मास्को और मध्य-एशियाई देशों तक आसानी से पहुंच जाएगा। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर हमेशा चाहेगा कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार का गठन हो जिसका इस्लामाबाद के साथ सहानुभूतिपूर्ण रिश्ता रहे। ऐसी सरकार के गठन से अमेरिका उससे पारंगत हो भी जाए तो वह परवाह नहीं करेगा। जाहिर है, यदि ऐसा होता है

बतंगड़ बेटुक

भारतीय राजनीति में भूकंपवाद

कोई भूकंप उठाती थी बड़ों-बड़ों की कंपकंपी छूट जाती थी। सबसे ज्यादा झटके समाचार कक्षों, प्रकाशों और समाचारवाची एंकर की उछलबच्चों के दिल-दिमाग में लगते थे। झटकों की तीव्रता उनकी हमलावारी मुद्राओं, भाव-भंगिमाओं, बोल-वाणियों, वाघप्रहारों-प्रतिप्रहारों में महसूस होती थी। भूकंपमापी पैमाने पर झटकों की तीव्रता 1 से 5 अंकों तक मापी जाती रही। तीव्रता दो-चार अंक और ऊपर चढ़ जाती तो सॉचिए क्या होता, कितना ध्वंस होता, जान-माल की कितनी हानि होती, कितने बड़े-बड़े नेता बेघरबार और न जाने कितने शणाथी शिविरों में पहुंच जाते। दिल्ली दहल जाती। भाजपा-कांग्रेस में से एक न एक जरूर जमींदोज हो जाती। साथ ही हुआ यह कि उसके उठाए हर भूकंप में उसके अपने महल का ही कोई न कोई कोना दरकता रहा, कोई न कोई स्तंभ दहता रहा। आप के पहलू में बैठकर जो लोग खांटी भूकंपवादी लगते थे, वे उसके पहलू से छिटककर भूकंपरोधी हो गए। कपिल मिश्रा जैसे कुछ स्तंभ तो भयानक प्रतिभूकंपवादी। शाजिया इलमी जैसे लोग भाजपा जैसी सुरक्षित इमारतों के स्तंभ बन गए, कुछ भ्रमित-दिग्भ्रमित, कुछ जड़ हो गए, कुछ भ्रष्टाचार विरोधी बोझिल जुए को कंधे से उतार कर पुनर्व्यव्रत हो गए और कुछ अपने-अपने मूल धंधों में

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी अलग राह अपना ली। अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कथित तौर पर कार्यकाल विस्तार की पेशकश मंजूर नहीं की और सेवानिवृति के फौरन बाद अपनी किताब में नोटबंदी को सबसे काला अध्याय बताया। उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक की संरक्षित राशि पर सरकार की नजर को जायज नहीं माना और इस्तीफा देकर हट गए लेकिन हाल के पांच राज्यों, खासकर हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के चुनावी नतीजों ने तो एनडीए सरकार का जैसे इकबाल ही खत्म कर दिया। उससे साबित हो गया कि सरकार के लिए विरोधी दल ही नहीं, रोजगार,

कृषि वगैरह के मुद्दे ही बड़े विपक्ष की भूमिका निभाने लगे हैं। ये वाकई सरकार के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं। कहा यह जरूर जा रहा है कि सरकार किसानों के लिए कोई नई राहत व्यवस्था और यूनिवर्सल इन्कम योजना जैसे कुछ कार्यक्रमों पर विचार कर रही है ताकि मुद्दों को ही विपक्ष की भूमिका निभाने से रोका जा सके। सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे में यह कैसे हो पाएगा, यह सवाल तो अलग है ही। लेकिन आखिरी चरण में आकर कुछ आधा-अधूरा-सा करने का खास फायदा नहीं हो पाता, इसकी मिसाल यूपीए सरकार के 2013 में लाता खाद्य सुरक्षा कानून से भी स्पष्ट है। यूपीए सरकार ने सोचा था कि उससे मनरेगा जैसा असर हो जाएगा लेकिन वैसा हो नहीं पाया।तो, सरकार के लिए प्रतिकूल होते माहौल में डर के औजार भी शायद ही काम करें, लेकिन कोशिशें जारी हैं। इसका सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिन सवालों पर कभी समाज में खास प्रतिक्रिया नहीं होती थी, या प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप नहीं लेती थी, ऐसे सवाल भी विवाद का विषय बनने लगे हैं। रामकथा और वेश्याओं का ही मामला लें। शायद ही किसी दौर में ऐसा देखा गया है कि सबको पवित्र करने वाले भगवान के अपवित्र हो जाने का ऐसा वितान ताना गया। शायद पहले दो दौर होता तो सबरीमला में हर उम्र की औरतों का प्रवेश भी कोई बड़ा सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जब ऐसा माहौल शिखर से पैदा होने लगे तो टकराहट के ये नए रूप हिसक भी होते जाते हैं। राजसत्ता की

भूमिका हमेशा ही टकराहटों को मिटाने में होनी चाहिए। लेकिन तंत्र जब हल ढूँढ़ने के बजाए समस्याएं पैदा करने लगे तो समाज में उसके अवस दिखेंगे ही। हाल में नोएडा में पार्क में धार्मिक आयोजन न करने का फरमान ही देख लीजिए। सरकार उचित जगह और अवसर मुद्देया करने के बदले सिर्फ पुलिसिया डंडा भांजती लगती है। जाहिर है, इससे समाज में ध्रुवीकरण और कट्टरता का माहौल ही पैदा होगा। लेकिन यह एहसास भी होना चाहिए कि ऐसे तमाम उपाय देश के सामने मौजूद रोजगार और कृषि जैसे संकट का हल नहीं दे सकते और जब तक उस दिशा में पहल नहीं होगी, किसी भी राजनैतिक दल को खास फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए डरने और डर का माहौल नहीं, आशा और उचित आकांक्षाओं का संचार करने से ही चुनावी फसल काटी जा सकेगी। न भूलें कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2014 के चुनाव ही हैं, जब लोगों ने बड़ी उम्मीद से अपना ऐतिहासिक जनादेश सुना दिया था।

२२

से अमेरिकी सैनिकों की वापसी भारत के सुरक्षा हितों पर असर डाल सकती है क्योंकि अफगान संकट के समाधान के बारे में नई दिल्ली का रूस तथा ईरान जैसे उसके क्षेत्रीय पारंपरिक सहयोगियों से अलग नजरिया है। रूस को आईएस का प्रेत डार है, और वह इससे लड़ने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। इसके लिए भारत का सहयोग चाहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि नई दिल्ली किस सीमा तक इसमें शरीक होगा। अफगानिस्तान को लेकर भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। भारत हमेशा चाहेगा कि काबुल में ऐसी सरकार का गठन हो जिसमें तालिबान के किसी भी धड़े का हिस्सा शामिल न हो। नई दिल्ली यह भी चाहेगा कि वहां ऐसी सरकार का भी गठन न हो जिसका झुकाव पाकिस्तान की ओर हो क्योंकि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग होगा तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन सकता है। अगर चीन, रूस और पाकिस्तान की पहल पर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होती है, तो इसका सीधा असर जम्मू-कश्मीर पर पड़ेगा जो वहां सक्रिय आतंकी संगठनों का हीसला बढ़ाने में मददगार होगा। जाहिर है कि ट्रंप की नईअफगान नीति जहां भारत की चुनौतियां बढ़ाने वाली हैं, वहीं पाकिस्तान को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है।

पद सरकारी कामकाज के लिए अवरोधक पद है, इसलिए इसे तत्काल खत्म किया जाए। आप से जिन्हें निकाला गया है, या जो स्वयं निकल गए हैं, उनके विचार-व्यवहार जनहित में नहीं हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जीवन से बेदखल किया जाए। प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव को वापस आप में भेजा जाए। इस शर्त पालन के साथ कि वे न कुछ सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे। कुमार विस के कवि सम्मेलन बंद कराए जाएं। आशुतोष की टेलीविजनिया तेजतंत्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो चैनल कपिल मिश्रा को बुलाएं उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये सब लोग आप की भ्रष्टाचार विरोधी प्रत्यक्ष मुहिम के परोक्ष भ्रष्टाचार हैं, इसलिए इनकी पथभ्रष्टता मिटाकर भ्रष्टाचार मिटाया जाए। आप का प्रवक्ता जो बोलें केवल उसे ही अंतिम सत्य समझा जाए और जो विरोध करे उसे निरस्त माना जाए। अगर प्रवक्ता कहे कि प्रस्ताव पास हुआ है, तो पास माना जाए और कहे कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो कैमरा फुटेंज के बावजूद प्रस्ताव को किसी भी सूत्र में पास न माना जाए। यह प्रस्तावी भूकंपवाद की मांग है। भारतीय राजनीति में भूकंपवाद अब स्थापित धारा है। याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे न्याय-दुलारे राहुल बाबा ने भी भूकंप लाने की कोशिश की थी, लेकिन यह दीगर बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पताकंप तक मानने से इनकार कर दिया था।

सार समाचार

टप कामकाज के लिये डेमोक्रेट्स को निशाना बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। सप्ताह भर से आंशिक रूप से टप पड़े सरकारी कामकाज को फिर से पटरी पर लाने के लिए हो रही बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेट्स को निशाना बनाकर टवीट कर रहे हैं। ट्रंप क्रिसमस के दौरान फ्लोरिडा के वलब में छुट्टियां मनाने के बजाए इस टप पड़े कामकाज को लेकर ह्वाइट हाउस में फंसे हुए हैं।

संघीय सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की समस्या नये साल में भी जारी रहने की आशंका है। वहीं दोनों दलों के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के दौरान इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने संघीय धन राशि में से अरबों डॉलर अमेरिका-मेक्सिको के बीच दीवार बनाने के लिए मांगी है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि वह इस धन का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए नहीं करने देंगे।

कोलम्बियाई राष्ट्रपति पर संभावित हमले की साजिश की जांच

बोगोटा (कोलंबिया)। कोलंबिया के अधिकारी राष्ट्रपति इवान डुक्यू पर संभावित हमले की साजिश के मामले में जांच कर रहे हैं। कोलम्बिया के विदेश मंत्री कार्लोस होम्?स ने बताया कि कोलम्बिया की खुफिया सेवाओं को डुक्यू की हत्या की साजिश रचे जाने की खबरें मिल रही थीं। उन्होंने बताया कि हाल ही में वेनेजुएला के तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों की चिंता और बढ़ गई है।

इन लोगों के पास से हथियार भी बरामद हुए थे। वेनेजुएला सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। होम्स ने टिवटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, ‘‘आपरा चिंता और अत्यंत निंदा के साथ, मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से खुफिया सेवाओं को राष्ट्रपति पर संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं।’’ उन्होंने कोलम्बियाई लोगों से राष्ट्रपति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर उसे साझा करने की अपील की है।होम्स ने अज्ञात विदेशी खुफिया एजेंसियों का भी सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया।

नकली डिग्री के सहारे उड़ा रहे थे हवाई जहाज, कंपनियों ने दिखाया बाहर का रास्ता

लाहौर- पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने सात पायलटों समेत 50 से अधिक कर्मचारियों के अनुबंध रद्द कर दिए हैं. ये सभी फर्जी डिग्री रखने के दोषी पाए गए थे. फर्जी डिग्रियां और सर्टिफिकेट के साथ पायलटों और केबिन सदस्यों के खिलाफ पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं. पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. संबंधित शैक्षिक संस्थानों ने इनकी डिग्रियां फर्जी पाई.’’ पीआईईए के प्रवक्ता मसहूद तजवर ने कहा कि फर्जी डिग्रियां रखने वाले सभी कर्मचारियों के मामलों की जांच शुरू कर दी गई है. सीएए ने कहा कि पीआईईए के 400 अन्य कर्मचारियों की डिग्रियों की जांच भी चल रही है. प्राधिकरण के महानिदेशक हसन बेग ने उन सभी पायलटों और कृ सदस्यों के लाइसेंस भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कारनामे होते रहते हैं जिन्हें पढ़कर लोग हैरान हो जाते हैं.

भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध के लिए ऐतिहासिक रहा 2018

वाशिंगटन (एजेंसी)।

व्यापार के मुद्दों पर विवाद के बावजूद, भारत और अमेरिका ने 2018 में अपनी रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने में ‘ऐतिहासिक’ प्रगति की। जापान के साथ पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने से लेकर पहली 2+2 वार्ता तक, भारत और अमेरिका इस साल अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गये। 2+2 के दौरान दोनों देशों ने लंबे समय से लंबित कॉमकासा समझौता पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत भारत अमेरिका से अधिक सवेदनशील और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीदी कर सकेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सितंबर में भारत को ‘टैरिफ किंग’ कहकर व्यापार विवाद छेड़ दिया था। हालांकि, दो महीने बाद, उन्होंने भारतीयों की अच्छे वार्ताकारों के रूप में प्रशंसा की जब दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार सौदे पर बातचीत शुरू की।

भारत उन कुछ देशों में से है, जिसने ट्रम्प

प्रशासन से ईरान प्रतिबंधों पर छूट हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान पर 2008 के मुंबई हमले के अपराधियों को न्याय के कठमरे में लाने के लिए

दबाव डाला और 26/11 हमले की साजिश रचने या हमले को अंजाम देने के किसी भी दोषी की किसी देश में गिरफ्तारी या सजा की सूचना देने के लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर के इनाम की घोषणा की। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिका की प्रधान उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा, ‘‘यह अमेरिका-भारत संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है क्योंकि हम हरके क्षेत्र में मजबूत संबंध स्थापित कर रहे हैं।’’ ट्रंप सरकार में अहम स्थान रखने वाली वेल्स ने कहा, ‘‘पिछले महीने, ब्यूनस आयर्स में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ पहली अमेरिका-भारत-जापान त्रिपक्षीय बैठक की, तीनों नेताओं के बीच हुई उस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जय’ कहा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी के

साथ बैठक के दौरान रणनीतिक साझेदारी की तीव्र प्रगति की समीक्षा की।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने सितंबर में पहले 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद को ‘तेजी से हो रही हमारी गहरी दोस्ती का प्रतीक’ बताया था।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के साथ 2+2 वार्ता की थी। इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा के साथ-साथ रक्षा, व्यापार, संचार इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण करार हुये। वेल्स ने कहा, ‘‘2+2 वार्ता, भारत को अमेरिका के एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में उल्लेख करने के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों पर आपसी सहयोग और स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र की हमारी साझी दृष्टि पर केंद्रित रहा था:- उन्होंने कहा, ‘‘-इस वार्ता का समापन संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ,



जो हमारी सेनाओं के बीच अधिक पारस्परिकता प्रदान करेगा, सूचना और खुफिया जानकारीयों के साझाकरण को बढ़ाएगा और ऊंच-श्रेणी की अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी तक भारत की पहुंच को सुनिश्चित करेगा।- उन्होंने कहा, ‘‘इस

समझौते को अंतिम रूप देना एक ऐतिहासिक कदम था और तब से, हमने कई और समझौतों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो हमारे सैन्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों को एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा।’’

किम जोंग उन ने लिया ऐसा फैसला, सुनकर दक्षिण कोरिया हुआ खुश

सियोल (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सियोल को एक पत्र भेज कर कोरियाई प्रायद्वीप के निस्त्रीकरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन से अगले साल ‘बार-बार’ मिलने का संकल्प लिया है. दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी. किम जोंग उन ने इस साल मून से तीन बार मुलाकात की. वे दो बार सीमा पर स्थित सीमा संघर्षविग्राम गैटो पनमुनजोम मे मिले थे और एक बार उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भेंट की थी. यह मुलाकाते सुलह की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए हुई थीं.



मून की सितंबर में प्योंगयांग की यात्रा के दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की जल्द से जल्द यात्रा करने का वायदा किया था. इसके बाद इस तरह की अटकलें थीं कि किम जोंग उन इस साल के अंत तक यह यात्रा कर सकते हैं. मून के

प्रवक्ता किम एयूइ क्योम ने कहा कि उनकी बहु प्रतीक्षित यात्रा अबतक हुई नहीं है. साल के खत्म होने के मौके पर किम जोंग उन के भेजे गए पत्र के मुताबिक इस यात्रा के नहीं होने का उत्तर कोरिया के शासक को ‘बहुत मलाल’ है.

क्योम ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर कोरिया के नेता ने भावी स्थितियों को देखते हुए सियोल की यात्रा करने को लेकर अपनी दृढ़ता को व्यक्त किया है. प्रवक्ता ने बताया कि किम जोंग उन ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रायद्वीप के निस्त्रीकरण के मुद्दे को हल करने के लिए 2019 में मून से बार-बार मिलने की मंशा भी जताई. अधिकारी ने यह नहीं बताया कि यह पत्र किस तरह से भेजा गया है.

भ्रष्टाचार मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने को चुनौती देंगे शरीफ

लाहौर (एजेंसी)।

पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने को इस हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। पीएमएल-एन प्रमुख के वकील ने रविवार को यह जानकारी दी। इस्लामाबाद की ब्रष्णचार रोधी एक अदालत ने पिछले सोमवार को 68 वर्षीय शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी लेकिन उन्हें फ्लैगशिप निवेश मामले में बरी कर दिया था। राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत (एनबीजे) ने शरीफ पर जुर्माना भी लगाया। शरीफ के वकील ख्वाजा

हरीस ने बताया, ‘हमने फैसले(शरीफ पर आए) के खिलाफ अपील का मसौदा लगभग तैयार कर लिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस हफ्ते अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘हमें अदालत से राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि जवाबदेही अदालत के फैसले में कई त्रुटियां हैं।’ सोमवार को दोषी ठहराए जाने के बाद शरीफ को एक रात रावलपिंडी की अड्डियाला जेल में बितानी पड़ी और अगले दिन उन्हें कोर्ट लखपत जेल भेज दिया गया। शरीफ के छोटे भाई एवं नेशनल असेंबली में विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ भी एक अन्य मामले में लखपत जेल में हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों भाई एक दूसरे से मिले क्योंकि वे एक ही बैरक में हैं।

कांगो : राष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी उम्मीदवारों का शांति समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार

किन्शासा (एजेंसी)।

कांगो में लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के दो प्रमुख उम्मीदवारों ने चुनाव की पूर्व संस्था पर शनिवार को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिससे अस्थिर देश में हिंसा भड़कने की आशंका पैदा हो गई है. मतदान से पहले तनाव बढ़ने के साथ मार्टिन फायुलू और फेलिक्स शिसेकेदी ने चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के मकसद वाले प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव अधिकारी इसकी विषय वस्तु में सुझाए गए बदलावों को करने में विफल रहे.

उन्होंने अफ्रीकी चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ संक्षिप्त बैठक के बाद

अपने फैसले की घोषणा की. अफ्रीकी देश में मतदाता इस बात का फैसला करने के लिए रविवार को मतदान में भाग लेगे कि राष्ट्रपति जोसफ कबीला का स्थान कौन लेगा. संसोधनों से संपन्न इस देश को वर्ष 1960 में आजादी के बाद से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए नहीं जाना जाता.

देश के स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के दो दिग्गज नेताओं और कबीला द्वारा उत्तराधिकारी चुने गए एमैनुएल रमजानी शादरी को नतीजों की घोषणा के बाद हिंसा रोकने के मकसद एक समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मनाया था लेकिन दोनों विपक्षी नेताओं ने इससे इनकार कर दिया.

अवैध रूप से भारत में रहने के दोषी 6 बांग्लादेशियों को 4 साल की कैद



ठाणे (महाराष्ट्र) (एजेंसी)।

स्थानीय अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने के दोषी छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएच मखरे ने पिछले सप्ताह दिए अपने आदेश में प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर एटीएस ठाणे ने मार्च, 2018 में भिवंडी कस्बे के एक अवामीय भवन पर छापेमारी कर छह बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो वैध दस्तावेजों/पासपोर्ट के बगैर रह रहे थे. एटीएस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार

किया, उनमें.. पियरो हुमनैल शेख (22), माणिक फरीद शेख (20), फारूक सैफुल आलम शेख (20), सुबुजी मुजीद शेख (22), मोहम्मद विलाल मोहम्मद महाबुल आलम शेख (22) और मोहम्मद अल

अमीन मोहम्मद यूसुफ मिया इस्लाम (20) शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ विदेशी और पासपोर्ट कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे. न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वे रोजगार की तलाश में भारत में घुसे थे. उन्होंने कहा, ‘‘उनके परिवार उन पर निर्भर हैं. यदि उन्हें जेल में बंद रखा गया तो उनका परिवार भुखमरी का शिकार होगा. इसलिए उन्होंने नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया है.’’ हालांकि अभियोजन पक्ष ने उनके लिए कड़ी सजा की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें चार साल के सामान्य कारावास की सजा सुनाई.

बांग्लादेश आम चुनाव : मतदान के दौरान हिंसा में 10 लोगों की मौत

ढाका (एजेंसी)।

बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार की सुबह मतदान शुरू होने के बाद हुई चुनावी हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है।सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों ही एक-दूसरे के समर्थकों और उम्मीदवारों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। सुबह आठ बजे मतदान शुरू होने के बाद राजधानी में ढाका सिटी सेंटर कॉलेज में सबसे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वोट डाला। हसीना के रिश्तेदार एवं पार्टी सांसद फजले नूर तापस इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।वोट डालने के बाद हसीना ने कहा, ‘‘मुझे हमेशा चुनाव में हमारी जीत का यकीन रहता है... मुझे अपने लोगों पर यकीन है और मुझे पता है कि वे हमें चुनेंगे ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके।’’

हसीना ने कहा, ‘‘उदारवादी बलों को जीत दिलाने के लिए लोग अवामी लीग के पक्ष में मतदान करेंगे।’’ एक ओर जहां हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद उनकी चिर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया का भविष्य अधर में लटक नजर आता है। सूचनाओं के मुतबिक जिया आंशिक रूप

से लकवाग्रस्त हैं। इस बीच, देश में विभिन्न जगहों पर हुई चुनावी हिंसा में अधिकारियों ने पांच लोगों के मरने की पुष्टि की है। अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार नौ लोगों की मौत हुई है जिनमें तीन अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, चुनावी हिंसा में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

देश में रंगमती के कावखाली में सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प में जुबो लीग के एक नेता की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। ‘जुबो लीग’ अवामी लीग की युवा शाखा है। ‘बीडीन्यूज24’ की खबर के अनुसार मृतक की पहचान जुबो लीग की घागरा यूनियन के महासचिव मोहम्मद बसोरुद्दीन के तौर पर हुई है। अवामी लीग के उप जिला महासचिव इश्शद मियां ने बताया कि घायलों को कावखाली उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। समाचार पोर्टल के अनुसार, चटगांव में बीएनपी का कार्यकर्ता मारा गया जबकि राजशाही में अवामी लीग के समर्थक की मौत हुई है। चुनावी हिंसा में अलग-अलग घटनाओं में दो राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए हैं। चुनाव के मद्देनजर रविवार को एक महत्वपूर्ण बांग्लादेशी समाचार चैनल ‘जमुना टीवी’ का प्रसारण बंद कर दिया गया।



रानी सती प्रोसेसर मील में करंट लगने से युवक की मौत

सूरत। रविवार की सुबह 6 बजे के करीब पांडेसरा के रानी सती प्रोसेसर फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने के समय युवक अकेला मील में काम कर रहा था। युवक के अन्य साथी उस समय चाय पाने गए हुए थे। जब वे चाय पीकर आए तो उन्होंने युवक के धायल अवस्था में वहां गिरा हुआ पाया। जिसके बाद उन लोगों ने मिल के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। परन्तु घटना की जानकारी मिलने के बाद भी कम्पनी के प्रबंधकों ने एम्बुलेंस तक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। करंट लगने की जानकारी जब युवक के घरवालों को मिली तो वे तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन परिजनों के पहुंचते पहुंचते डेढ़ घंटे से अधिक का समय बीत गया। साढ़े सात बजे के करीब लोगों ने आटो रिक्शा से युवक को निकट के मुव हास्पिटल ले गए। जहां हास्पिटल के डाक्टरों ने भर्ती लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में परिजनों ने 108 एम्बुलेंस

बुलाकर युवक को न्यू सिविल हास्पिटल ले जाने का प्रयास किया परन्तु 108 एम्बुलेंस वालों ने यह कहकर ले जाने से इंकार कर दिया कि एम्बुलेंस से मृतक को नहीं ले जाया जा सकता। इस घटना की जानकारी मिलते ही वी आई पी रोड स्थित दैनिक भास्कर के कार्यालय के सामने मूव हास्पिटल के सामने भीड़ इकट्ठ हो गई। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बुला ली। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। जिसके बाद शाव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हास्पिटल ले जाया गया। युवक की मौत पर परिजनों ने युवक के लिए मुआवजे की मांग करते हुए लाश का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि जब तक मिल मालिक द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता हम लोग युवक का शव मिल के



मृतक- दिनेश नन्हे लाल मौर्या

अंदर रखकर प्रदर्शन करेंगे। परन्तु पुलिस द्वारा मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिए जाने पर लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए।

पुलिस की सूझ बुझ से मामला बिगड़ने से बचा
हाल ही में पांडेसरा में संचालित साई क्लिनिकल सेंटर

में मरीज के मौत पर हुए बवाल तथा हास्पिटल में हुई तोड़ फोड़ की घटना को ध्यान में रखकर पुलिस ने सूझ बुझ का परिचय देते हुए मामले को बिगड़ने से बचा लिया। प्रत्यक्ष दार्शियों का कहना है कि कुछ लोग मानवाधिकार संस्था के नाम पर हंगामा खड़ा करना चाहते थे परन्तु पुलिस ने उनकी मंशा को भांपते हुए परिजनों को हर संभव

सहायता प्रदान करने की बातकर शांत कर लिया। पुलिस ने कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी मंशा पर पानी फेर दी। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। देर रात तक युवक का अंतिम संस्कार अश्विनी कुमार शमसान घाट पर कर दिया गया।

मिल के प्रबंधकों की लापरवाही बनी मृत्यु का कारण

पांडेसरा के रानी सती प्रोसेसर में करंट लगने से 28 वर्षीय दिनेश नन्हेलाल मौर्या की मौत हो गई करंट लगने की घटना के घंटों बाद भी मिल मालिक शशिभाई उनका बेटा अभिलाष तथा मैनेजर संजय गांधी ने अस्पताल पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। अस्पताल पहुंचने में अगर शीघ्रता दिखाई गई होती तो शायद दिनेश की मौत नहीं होती। दिनेश के परिवार में उनकी 3 साल की बच्ची तथा डेढ़ साल का बेटा है। पति के असमय साथ छोड़ जाने से पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है।

पतंग उड़ाते हुए दो बच्चे पहुंचे अस्पताल, हालत गंभीर

सूरत। पतंगबाजी एक ऐसा शौक है जिसमें बच्चे ही नहीं बड़े बड़े भी इतने मस्त हो जाते हैं कि दुर्घटना को न्यौता दे बैठते हैं। पतंगबाजी के दौरान ऊपर से गिरना, सड़कों पर वाहनों की या बिजली तार की चपेट में आना। ऐसी अनेक दुर्घटनाओं को देखने के बावजूद लोग बेफिक्र होकर पतंगबाजी से बाज नहीं आते। सूरत में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें पतंगबाजी के दौरान डोर हाईटेशन तार के संपर्क में आ गया और दो बच्चे गंभीर रूप

से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र मूल के आर्यन और हिमांशु नामक दो बच्चे सूरत के भेस्तान क्षेत्र में रहते हैं। सूरत के सरकारी अस्पताल कक्षा 3 के छात्र आर्यन और हिमांशु पतंग उड़ा रहे थे। उस वक्त पतंग की डोर वहां से गुजर रहे हाईटेशन बिजली तार को छू गई। जिसमें एक किशोर बुरी तरह से झुलस गया, जबकि दूसरा भी घायल हो गया। दोनों बच्चों को सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



सूरत। कुबेर नगर मंदिर के रजत जयंती महोत्सव पर रविवार को भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव का शुभारंभ पोथी तथा शोभायात्रा से की गई। महोत्सव के दौरान श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह, गोवर्धनपूजन, अन्नकुट उत्सव के साथ सम्पन्न होगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

सूरत। अगले तीन दिनों में विदा होने वाला वर्ष 2018 पश्चिम रेलवे के लिए काफी अच्छा वर्ष सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें बेहतर यात्री सेवाओं एवं सुविधाओं के अलावा बेहतर भविष्य के लिए अपग्रेडेड आधारभूत संरचनाओं सहित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं। खासकर वर्ष के दौरान बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी रविंद्र भाकर के अनुसार इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में 25 दिसम्बर, 2017 से शुरू हुई भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन का 1 जनवरी, 2018 से विचार तक परिचालन, गोरेगाँव तक हार्बर लाइन का विस्तार, 2 नई महिला विशेष लोकल ट्रेनें, गैर उपनगरीय

खंड के लिए यूटीएस की शुरुआत, उधना-जलगाँव दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण परियोजना की पूर्णता, डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर एवं रो-रो सेवा की शुरुआत, वडोदरा में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी एनआरटीआई को लोकार्पण तथा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा के निकट केवडिया में माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन मुख्य रूप से शामिल रहा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान महिला एवं बाल सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के कारण उपाय सुनिश्चित किए गए, क्योंकि माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2018-19 को महिला एवं बाल सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया है।

गुजरात कांग्रेस में मचा घमासान, सूरत कांग्रेस के 12 पदाधिकारियों का इस्तीफा

सूरत। गुजरात कांग्रेस में फिर एक बार घमासान छिड़ गया है वरिष्ठ नेताओं की हाल में हुई बैठक को भाजपा के समर्थन में एक साजिश बताया। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी को मजबूत करने के बजाए उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं पर ऐसे आरोप लगानेवाली पत्रिकाएं वितरित की गई हैं और इसे जूनागढ़ के एक कार्यकर्ता के नाम से वितरित किया गया है। गुजरात कांग्रेस में दो गुटों के बीच कलह फिर एक बार सामने आ गई है। बता दें कि हाल ही

में गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोठवाडिया के घर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसका जूनागढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता की पत्रिकाओं में उल्लेख किया गया है। पत्रिका में कहा गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा को मदद के लिए एक साजिश रच रहे हैं। इस बारे में पार्टी हाईकमांड को भी अवगत कराया गया है। दूसरी ओर सूरत में कांग्रेस के नए संगठन के ऐलान के बाद आंतरिक कलह तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा के आदेश पर सूरत कांग्रेस

प्रमुख बाबु रायका ने 175 जितने नए पदाधिकारियों की सूची जारी की। इन नई नियुक्तियों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा और सूरत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जवाहर उपाध्याय समेत 12 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सूरत प्रमुख बाबु रायका को भेजे इस्तीफे में जवाहर उपाध्याय में लिखा कि सूरत शहर कांग्रेस ढांचे के बारे में चर्चा के लिए तीन-चार बार अनुरोध किया। लेकिन सूरत कांग्रेस प्रमुक्त ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा से भी

चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जवाहर उपाध्याय के मुताबिक सूरत कांग्रेस का नया ढांचा बेहद कमजोर और निराशाजनक है। गौरतलब है सूरत कांग्रेस में कदीर और जवाहर दो गुट हैं और नए ढांचे में जवाहर गुट के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया गया है। नए संगठन में नवसारी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके मकसूद मिर्जा को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा नगर पार्षद भूपेन्द्र सोलंकी और प्रवक्ता संजय पटवा को भी हटा दिया गया है।



सूरत। स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं में जागरूता लाने के लिए रविवार को शहर के वराछ क्षेत्र में वराछ मेराथन का आयोजन किया गया। जिसमें 6 हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखते रखते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाती हैं। जिसके चलते महिलाओं को बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में सभी आयु वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। मेराथन दौड़ पूरा कैनाल रोड से आरंभ होकर महाराजा फार्म पहुंचकर समाप्त हुई 8 किमी लम्बी दौड़ में शामिल होकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है।